IRCON/SECY/STEX/124 **8th November, 2024**

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 **बीएसई लिमिटेड** लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई– 400001 Scrip code / ID: **541956 / IRCON**	**National Stock Exchange of India Limited** Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: **IRCON**

Sub.: Publication of unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended on 30th September, 2024/ 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) का प्रकाशन

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

A copy of unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended on 30th September, 2024, as approved by the Board at its meeting held on Thursday, 7th November, 2024, as published in today's newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

आज के समाचार पत्रों (अंग्रेजी और हिंदी में) में प्रकाशित, 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) की प्रति, जो कि गुरुवार, 7 नवम्बर, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित है, आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,
भवदीय,

ANKIT JAIN
2024.11.08 10:47:35 +05'30'

(अंकित जैन)/ (Ankit Jain)
अनुपालन अधिकारी/ Compliance Officer
सदस्यता क्र./ Membership No.: A35053

कांग्रेस की 'दिल्ली न्याय यात्रा' राजघाट से आज होगी शुरू

70 विधानसभाओं के हर बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य, चार दिसंबर को खत्म होगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत राजघाट से होगी। माह भर तक चलने वाली इस यात्रा के चार चरण होंगे। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता जनसंवाद भी करेंगे एवं जनता के बीच ही रात्रि प्रवास भी करेंगे।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए 'दिल्ली न्याय यात्रा' शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अपने कार्यक्रम के आधार पर पहले चरण में

इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ करीब 300 कार्यकर्ता होंगे शामिल।

शामिल होने के आसार हैं। यह यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभाओं के प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने के कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के हर घर के दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। राजघाट से शुरू होकर दिल्ली गेट, आसफ अली रोड, तुर्कमान गेट, सीताराम बाजार, हौज काजी चौक, कटरा बारियान से होते फतेहपुरी पहुंचकर पहले दिन की यात्रा समापन होगी।

आप और भाजपा दोनों संविधान विरोधी

यादव ने कहा कि 11 वर्षों में भाजपा ने महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने में निष्क्रियता दिखाकर पिछले 75 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। लोगों के अधिकारों की रक्षा करने लिए बनाए गए लोकतंत्र को कमजोर बनाने का काम किया है, वहीं आम आदमी पार्टी झूठे वादों करके सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों संविधान विरोधी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने को अपना नैतिक कर्तव्य माना है।

परेशानी

नई दिल्ली में गुरुवार को धुंध के कारण कम दृश्यता के बीच सड़क पर चलते वाहन।

प्रदूषण के कारण नहीं हो रहा ठंड का अहसास

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

बढ़ते प्रदूषण के कारण इस बार ठंड का वो अहसास नहीं हो पा रहा है जो हर साल हुआ करता था। हाल यह है कि दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में एकमात्र रिज इलाका ही ऐसा है, जहां सामान्य से कम तापमान लगातार दर्ज किया जा रहा है। जबकि पीतमपुरा व राजघाट में सामान्य से चार से पांच

सिर्फ रिज क्षेत्र में सामान्य से एक डिग्री कम रहा तापमान जबकि पीतमपुरा सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

डिग्री अधिक बीते एक सप्ताह से न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पीतमपुरा में सर्वाधिक सामान्य से सात डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जोकि 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद राजघाट में सामान्य से छह डिग्री अधिक 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से सिर्फ रिज क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा है जहां सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है, गुरुवार को यहां सामान्य से एक डिग्री कम 14.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली का अधिकतम तापमान गुरुवार को 31.7 रहा जबकि न्यूनतम 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बिजली दरें बढ़ाने का भाजपा करेगी विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

बिजली की दरों में बढ़ोतरी की किसी भी कोशिश का भाजपा ने विरोध करने का फैसला किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब तक राजधानी में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों का कैग आडिट नहीं हो जाता तब तक सरकार को बिजली दरों में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बिजली आपूर्ति के काम को निजी हाथों में सौंपने के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जो दावा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है।

बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसइएस एवं बीवाइपीएल में भारी आर्थिक धांधली के आरोप। खातों की कैग जांच कराने की मांग।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बिजली आपूर्ति कंपनियां डिस्काम बीएसइएस एवं बीवाइपीएल में भारी आर्थिक धांधली चल रही है। इन कंपनियों के खातों की कैग या न्यायिक जांच करवाना जरूरी है। पावर डिस्काम में 51 फीसद की साझीदार निजी कंपनियों के साथ ही 49 फीसद की साझीदार दिल्ली सरकार की भूमिका भी बराबर की जिम्मेदार है और दोनों ने मिल कर पावर डिस्काम को दिवालियापन की कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है।

सामूहिक बलात्कार के तीन आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता का इलाज जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

दिल्ली पुलिस ने सराय काले खां में मानसिक रूप से अस्वस्थ ओडीशा की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। दस अक्तूबर को कथित सामूहिक बलात्कार के बाद पीड़िता का दिल्ली के एम्स में उपचार किया जा रहा है। वह अपने परिवार को बताए बिना नौ मई को दिल्ली आ गई थी जिसके बाद परिवार ने पुरी में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

दक्षिणी-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह के मुताबिक उन्हें 11 अक्तूबर को सराय काले खां इलाके में एक महिला के खून से लथपथ पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पीड़िता को बहुत बुरी स्थिति में पाया गया। पीड़िता इतनी सहमी हुई थी कि वह कुछ नहीं बता पा रही थी। उसे मेडिकल जांच तथा देखभाल के लिए एम्स के 'ट्रामा सेंटर' ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर पीड़िता ने वहां मौजूद चिकित्सक को बताया कि तीन व्यक्तियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है।

पुलिस ने बताया कि 11 अक्तूबर को शराब के आदी आरोपी प्रमोद उर्फ बाबू ने अपनी दुकान बंद की और शराब पीने लगा। उसने पास में बैठी एक लड़की को देखा।

21 दिन में 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले

युवती के साथ दरिंदगी करने वाले आटो चालक प्रभु महतो का आटो राजघाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। आटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस प्रभु महतो तक पहुंच गई। इसके बाद प्रमोद उर्फ बाबू व मोहम्मद शमसुल को पकड़ लिया। दक्षिण-पूर्व जिले के वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने 21 दिन में 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 150 से ज्यादा आटो का सत्यापन किया। इसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

शारीरिक रूप से दिव्यांग शमसुल भी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर लड़की को जबरन घसीटकर सुनसान इलाके में ले जाकर दरिंदगी की। इस दौरान वहां से आटो लेकर गुजर रहे आरोपी प्रभु महतो ने घटना को देखा और अपराध में शामिल हो गया। आरोपी प्रभु महतो ने फिर से लड़की को अपने आटो में जबरन बैठाया और उसके साथ बलात्कार किया।

जेएनयू के अधिकारी ने कहा

राजदूतों की संगोष्ठियां रद्द करने के लिए दबाव डाला गया

नई दिल्ली, 7 नवंबर (भाषा)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा पश्चिम एशियाई देशों के राजदूतों की संगोष्ठियां को कथित रूप से रद्द किए जाने को लेकर हुए विवाद के बीच, विश्वविद्यालय की एक पूर्व कार्यक्रम समन्वयक ने पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन पर कार्यक्रम रद्द करने के लिए दबाव डाला गया था।

पूर्व कार्यक्रम समन्वयक सीमा बैद्य ने विश्वविद्यालय के एक अधिकारी द्वारा उनकी निजी जानकारी कथित तौर पर लीक किए जाने के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जेएनयू से सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की। ईरान, फिलीस्तीन और लेबनान के राजदूतों के तीन कार्यक्रमों को जेएनयू ने कोई कारण बताए बिना पिछले महीने कथित तौर पर रद्द कर दिया गया था। ये तीनों राजदूत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बोलने वाले थे। पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र (जहां राजदूतों को बोलना था) जेएनयू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआइएस) के अंतर्गत कार्य करता है। एसआईएस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। बैद्य को अध्ययन केंद्र के साथ संवादहीनता के लिए दोषी ठहराया गया था और उनकी जगह किसी अन्य की नियुक्ति की गई थी।

एमसीडी ने संपत्ति कर संग्रह को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल बनाया

नई दिल्ली, 7 नवंबर (संवाददाता)।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्लीवासियों की सुविधा व प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संपत्तिकर संग्रह को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। एमसीडी ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जो डीएमसी अधिनियम (संशोधन) 2003 के अनुसार धारा 175, 123ए व बी, 123डी, 154, 156(1), 446, 152ए और मूल्यांकन आदेशों के तहत सभी नोटिसों को इलेक्ट्रानिक रूप से जारी करने की अनुमति देती है। करदाता अब इन नोटिसों को डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं आनलाइन जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एमसीडी ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है।

पांच हजार रिश्वत लेते दिल्ली पुलिस की महिला उपनिरीक्षक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 7 नवंबर (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस सर्तकता यूनिट ने बवाना थाना में तैनात दिल्ली पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर को पांच हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पूजा चौहान बलात्कार के एक मामले में आरोपी को जमानत दिलाने में सहयोग के नाम पर रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ी गई।

सर्तकता विभाग के मुताबिक छह नवंबर को शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज है। पूजा इस मामले में जांच अधिकारी है। उसके पति की जमानत की अर्जी पर पांच नवंबर को दिल्ली के एक अदालत में सुनवाई होनी थी। पुलिस अधिकारी पूजा ने आरोपी पर दबाब बनाया कि अगर शिकायतकर्ता ने उसे कुछ पैसे दे दिए तो फिर उसके पति की जमानत नहीं हो पाएगी। पूजा ने एक अधिवक्ता से भी जमानत दिलाने के नाम पर मिलने कही और जब पीड़ित मिले तो उससे डेढ़ लाख रुपए मांगा गया। पीड़ित ने जब पैसे देने में असमर्थता व्यक्त की तो फिर उससे पचास हजार और पाद में बीस रुपए में सौदा तय हो गया। दस हजार रुपए उसने दे दिया लेकिन पूजा बार-बार अन्य रकम की व्यवस्था करने के लिए दबाब देने लगी। उसने सर्तकता विभाग में शिकायत देकर पूजा को पकड़वाने के लिए साथ दिया और फिर रिश्वत की रकम के साथ उसे गिरफ्तार करवा दिया।

उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका का निस्तारण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1988 में सलमान रुश्दी के विवादास्पद उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर प्रतिबंध लगाने के तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अधिकारी संबंधित अधिसूचना पेश करने में विफल रहे हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वह मौजूद ही नहीं है। अपने आदेश में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका, जो 2019 से लंबित थी, इसलिए निष्फल थी और याचिकाकर्ता कानून में उपलब्ध पुस्तक के संबंध में सभी कार्रवाई करने का हकदार होगा।।

याचिकाकर्ता संदीपन खान ने अदालत में तर्क दिया था कि वह पुस्तक का आयात करने में असमर्थ हैं, क्योंकि पांच अक्तूबर 1988 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार देश में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यह अधिसूचना न तो किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध थी और न ही किसी संबंधित प्राधिकारी के पास थी। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है, और इसलिए, हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते और रिट याचिका को निष्फल मानकर उसका निपटारा करते हैं।

इरकॉन

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए एकल/समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल						समेकित					
	30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	2,298.86	2,180.48	2,883.64	4,479.34	5,509.28	11,950.40	2,447.52	2,287.13	3,033.27	4,734.65	5,797.11	12,513.65
निवल लाभ/(हानि) (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व और विशिष्ट मदों के उपरांत)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
कर उपरांत निवल लाभ	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.92	224.03	250.78	429.95	438.15	929.51
लाभ निम्नलिखित को समर्पित है :												
मूल के स्वामी	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.95	224.02	250.73	429.97	438.09	929.57
अनियंत्रित हित	-	-	-	-	-	-	(0.03)	0.01	0.05	(0.02)	0.06	(0.06)
कुल समग्र आय	201.34	176.84	237.01	378.18	399.18	862.39	205.02	224.36	257.35	429.38	445.23	928.98
इक्विटी शेयर पूँजी	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
मूल के स्वामियों को समर्पित अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)						5,583.66						5,682.82
प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं)												
(प्रत्येक ₹ 2/- अंकित मूल्य)												
(क) बेसिक (₹ में)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88
(ख) डाइल्यूटिड (₹ में)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88

टिप्पणियाँ :

1. उपर्युक्त एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई है और निदेशक मंडल ने 7 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इसका अनुमोदन किया है। कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के द्वारा 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं छः माह के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा कर ली गई है।
2. एकल और समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अधीन यथा अधिसूचित, इसके अधीन संगत नियमों के साथ पठित और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षायें) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 33 तथा अन्य लागू मान्यता प्राप्त लेखांकन व्यवहारों और नीतियों के तहत भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटन अपेक्षायें) विनियम, 2015 के विनियम 33, यथा संशोधित, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार है। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई (www.bseindia.com), एनएसई (www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।
4. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत/पुनः निर्मित किया गया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08453476

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 07 नवम्बर, 2024

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली-110017; फोन: +91-11-26530266; फैक्स: +91-11-26522000/26854000
ई-मेल: investors@ircon.org; वेबसाइट: www.ircon.org; कॉर्पोरेट आईडेंटिटी नम्बर : L45203DL1976GOI008171

Ruckus in J&K House: Some MLAs bring another 'tougher' special status resolution

BASHAARAT MASOOD
SRINAGAR, NOVEMBER 7

A DAY AFTER the Jammu and Kashmir Assembly passed a resolution moved by the Omar Abdullah government seeking dialogue for restoration of J&K's special status, five non-BJP Opposition MLAs submitted a resolution to the Speaker that "unequivocally" rejected the decisions of August 5, 2019.

Unlike Wednesday when most of the non-BJP Opposition parties supported the government resolution, with riders, the MLAs attacked the ruling NC, hinting that it had an understanding with the Centre.

The five legislators – People's Conference's Sajad Lone, Peoples Democratic Party's Waheed Para and Fayaz Mir, and Independent MLAs Sheikh Khursheed Ahmad and Shabir Ahmad Kullay – said their 'People's Resolution', which mentioned the contentious Articles 370 and 35 A, stemmed from public anger over the one moved by the Omar government.

Thursday also saw a scuffle break out in the Assembly after Independent legislator Sheikh Khursheed Ahmad, the brother of MP Engineer Rashid, brought a banner that read: "We demand restoration of Article 370 and 35A and the release of political prisoners". BJP legislators jumped into the Well of the House to snatch the banner, after which Sajad Lone, Waheed Para and NC's Hilal Lone followed them into the Well to support Ahmad. Six BJP leaders were marshalled out of the House on the directions of the Speaker, but as the ruckus continued, the House was adjourned for the day.

During the ruckus in J&K Assembly, Thursday. *Shuaib Masoodi*

It was amid this pandemonium that the five MLAs submitted their resolution to Speaker Abdul Rahim Rather. It said: "This House strongly condemns the unconstitutional and unilateral abrogation of Article 370 and Article 35A, along with the enactment of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019, by the Government of India. These actions stripped Jammu & Kashmir of its special status and statehood, undermining the foundational guarantees and protections originally accorded to the region and its people by the Constitution of India."

It added: "This House unequivocally demands the immediate restoration of Article 370 and Article 35A in their original, unaltered form, and calls for the reversal of all changes introduced by the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019. We further urge the Government of India to respect the constitutional and democratic sanctity of Jammu & Kashmir by reinstating all special provisions and guarantees intended to preserve its distinct identity, culture, and political autonomy."

The MLAs said they would welcome it if the NC brought a resolution like theirs or supported it.

"We don't want to criticise, we supported them (the NC) when they brought the resolution (on Wednesday), but it is a weak resolution... It is humiliation of the people of J&K, betrayal of them... a medley of words, nothing else," Lone said, addressing the press after the House adjourned for the day. The adjournment immediately followed the submission of the resolution by the five MLAs, with proceedings interrupted due to slogans and counter-slogans by BJP and NC.

Lone said the adjournment seemed "a fixed match" between the BJP and NC. "First the BJP shouts. When they stop, the NC starts shouting," he said. "Either they support us or they bring this resolution and we will support it. Or let them tell us what is the difference between their resolution and our resolution. If they support this (new resolution), I will apologise, but if they don't, I will call it a fixed match."

PDP's Para, who had separately moved a resolution Monday seeking special status, also attacked the NC, saying: "From 1947 till now, whenever the Centre has snatched our powers and needed to normalise the situation – whether it was special status, or downgrading the Prime Minister (Wazir-e-Azam) to Chief Minister – the NC has done it for them... They said that the first business (of the House) would be a resolution on 370, but they brought a resolution on statehood. That was not the will of the people... They are now normalising a historical betrayal." Lone, Para and Ahmad urged the people to "come on social media to endorse" their new resolution.

Pulled up by top court, govt doubles stubble burning fine

NIKHIL GHANEKAR
NEW DELHI, NOVEMBER 7

TWO WEEKS after the Supreme Court pulled up the Centre for rendering the Environmental Protection Act, 1986 "toothless", the Union Ministry of Environment Wednesday doubled penalties for stubble burning and notified new rules under the Act for filing complaints and holding an inquiry.

The Centre notified the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilisation of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024, for doubling environmental compensation imposed for stubble burning.

The amended rules were notified under the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021, and will come into effect immediately without a draft being placed in the public domain for consultation.

On October 23, hearing a plea, a bench of Justices Abhay S Oka, Ahsanuddin Amanullah, and Augustine George Masih had noted that after the Jan Vishwas Act was passed, prosecution for violation was replaced by penalties but the Rules were not notified to give this provision an effect.

The bench also said that the rates fixed by NGT for environmental compensation need not be followed blindly and directed the government to exercise powers under the CAQM Act, 2021 to prescribe proper rates of compensation. "The substituted Section 15 has been rendered completely ineffective due to inaction on the part of the Government of India. Neither the Rules are framed to support the said provision nor the appointment of adjudicating officers as provided in Section 15C has been made..." the bench had said.

The new rules will come into effect immediately. *File*

"As the adjudicating officers are not appointed under Section 15C, the law-enforcing machinery cannot impose penalties under Section 15. In the absence of machinery created by the Government of India, Section 15 as substituted has become toothless," it had said.

Under the new rules, fines were doubled from ₹2,500 to ₹5,000 for farmers holding less than two acres of land, and ₹10,000 from ₹5,000 for two to five acres of land. Those holding more than five acres have to cough up ₹30,000 up from ₹15,000.

The penalties were first fixed by the National Green Tribunal's principal bench in a November 2015 order. Taking cognisance of the contribution of stubble fires to air pollution in Delhi-NCR, the NGT had ordered Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi-NCT governments to impose these penalties.

Additionally, the NGT had also stated in its 2015 order that the states would provide farmers machines to remove, collect and store crop residue, based on their land holdings.

The Centre also notified the Environment Protection (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024 Wednesday, which lays down the process of filing complaints with pollution control boards, the Commission for Air Quality Management, and offices of the Union Environment Ministry. It also laid out the process of holding an inquiry on complaints against environmental pollution and adjudication of the complaints.

Condemning the decision, farmer unions in Punjab accused the BJP-led NDA government of preferential treatment to industries that contribute to pollution. Bharti Kisan Union (Ekta Ugrahan) general secretary Sukhdev Singh Kokrikalan dubbed the move "anti-farmer".

"By doubling the fines, will they be able to intimidate farmers? I don't think so. Even if they increase it by 10 times, farmers won't pay. Industries contribute to 51% of the pollution," said Kokrikalan. Kisan Mazdoor Morcha coordinator Sarwan Singh Pandher blamed the state government for being unable to provide "even 30% of crop residue management machines." **WITH INPUTS FROM RAAKHI JAGGA**

CJI'S LAST WORKING DAY IN OFFICE

Is AMU a minority institution? 7-judge bench to rule today

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, NOVEMBER 7

A SEVEN-JUDGE Constitution Bench of the Supreme Court will rule Friday on whether the Aligarh Muslim University (AMU) can be considered a minority institution under Article 30 of the Constitution.

The bench, headed by CJI D Y Chandrachud (Friday is his last working day in office), will decide on a reference that arose from a 2006 verdict of the Allahabad High Court which held that the AMU, established through an imperial legislation in 1920, was not a minority institution.

Without minority status, AMU will have to begin implementing reservation policies for both teachers and students in a similar manner as other public universities. If this status is granted, the university can provide up to 50% reservation for Muslim students. Currently, AMU does not follow any reservation policies of the state. However, it does have an internal reservation policy, where 50% of seats are reserved for students who have studied in its affiliated schools or colleges.

The bench, which also includes Justices Sanjiv Khanna (the incoming CJI), Surya Kant, J B Pardiwala, Dipankar Datta, Manoj Misra and S C Sharma, heard arguments over the course of eight days between January 10 and February 1 this year.

This issue was decided once before by the Supreme Court. In 1967, in the case of S. Azeez Basha v. Union of India, a five-judge Constitution Bench held that AMU was not a minority institution. It referred to the Aligarh Muslim University Act, 1920, which established the university and held that AMU was neither established nor administered by the Muslim community – a requirement for minority educational institutions under Article 30 (1) of the Constitution.

An amendment to the AMU Act in 1981 stated that the university had been "established by the Muslims of India". In 2005, the university, claiming minority status, reserved 50% of seats in postgraduate medical courses for Muslim students.

The Allahabad HC struck down the reservation policy and the 1981 amendment, holding that AMU was not a minority institution. This verdict was challenged in the Supreme Court, and in 2019 the case was referred to a seven-judge bench to decide if the verdict in S. Azeez Basha v. Union of India required reconsideration.

The Centre, which withdrew from the appeal in 2016 and is now arguing against AMU's minority status, stated that AMU never possessed minority status.

Resolution disrespect to Constitution, SC verdict: Irani

New Delhi: Attacking the INDIA bloc and the Congress over the passage of a resolution in the J&K Assembly to reinstate Article 370, former Union minister and BJP leader Smriti Irani said Thursday that the INDIA bloc was trying to disrespect the Constitution, the Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370, and also trying to stoke separatism and militancy in Kashmir.

She sought to know whether the Congress leadership and the Nehru-Gandhi family was supporting terrorism or development in J&K.

"Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by Congress-led INDI Alliance to bring to the floor of the House a resolution that is against the Indian Constitution... The resolution brought by INDI alliance led by Congress brings to the fore many questions. Does it stand against the rights of Dalits, tribals, children and women?... Congress leadership, particularly the Gandhi family, needs to answer — do they stand for terrorism and stand against the development of J&K?" **ENS**

Wanted to bring resolution that Govt can't ignore: Omar

NAVEED IQBAL
SRINAGAR, NOVEMBER 7

WITH REGIONAL parties criticising the National Conference's resolution on restoration of special status, J&K CM Omar Abdullah Thursday said his party wanted to bring a resolution that "cannot be ignored by the Centre" and forces them to initiate dialogue.

The language of the NC's resolution expressing "concern" over the "unilateral move" by the Centre to revoke J&K's social status has been criticised by regional parties as being too vague, even as the BJP calls it "illegal".

On the sidelines of an event in Ganderbal on Thursday, Omar said, "We could have brought a resolution on the first day (of the Assembly session) that they (the Centre) would have thrown into the trash; what would that achieve? We wanted to raise a voice in the Assembly that forces the Centre to hold a dialogue with us. One that they cannot ignore."

He added that by passing the resolution in the Assembly, "NC has told the world what we want and we will achieve."

J&K CM Omar Abdullah in the Assembly, Thursday. *PTI*

Emphasising that the Assembly has sent a message that the events of August 5, 2019 are unacceptable to the people of J&K, he said, "It was done without our consent, consultation or our wishes." Addressing criticism that the resolution was not brought on the first day of the Assembly session Monday, he said, "We are aware of the rules and regulations and we know how to bring these things through the Assembly."

SC restores DRI officers' powers to recover dues under Customs Act

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, NOVEMBER 7

IN A significant decision, the Supreme Court overturned the apex court's 2021 verdict Thursday and ruled that Directorate of Revenue Intelligence (DRI) officers have the authority to issue notices and recover dues under the Customs Act, 1962.

Allowing a petition seeking review of the top court's decision in 2021 in Canon India Pvt Ltd vs Commissioner of Customs filed by the customs department, a bench headed by CJI D Y Chandrachud and comprising Justices J B Pardiwala and Manoj Misra passed the order. Justice Pardiwala authored the 162-page ruling.

In 2021, a three-judge bench headed by then CJI Sharad Bobde had held that for a DRI officer to exercise the functions of a Customs officer, the Centre must specifically exercise its power to entrust such functions on "other officers" under Section 6 of the Customs Act.

"Subject to the observations made in this judgment, the officers of DRI, Commissionerates of Customs (Preventive), Directorate General of Central Excise Intelligence and Commissionerates of Central Excise and other similarly-situated officers are proper officers for the purposes of Section 28 and are competent to issue show cause notice thereunder," the bench held on Thursday.

"The petition seeking a review of (the) Canon India (judgment) is allowed for the following reasons.... In other words, the judgment in Canon India was rendered without looking into the circular and notification, therefore seriously affecting the correctness of the same. The decision in Canon India failed to look into the statutory scheme," it said.

The bench noted that in 1999, a circular was issued by the CBEC, New Delhi that empowered officers of the DRI to issue notices under Section 28 of the Customs Act. The court also found that a notification was issued in 2011 which stated that DRI officers could perform the functions of a "proper officer" under the Customs Act.

The court ordered that all pending cases relating to show-cause notices under Section 28 of the Customs Act must now be decided according to this verdict.

EXPRESS Careers

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
Regd and Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Web: www.grse.in, (CIN: L35111WB1934GOI007891)

EMPLOYMENT NOTIFICATION NO. 2024/09 (O)

GRSE Ltd. is one of the Premier Schedule –A Mini Ratna, Category -I, Defence PSU Shipyards of India. It is effectively contributing to the Defence preparedness of the country by building different sophisticated and state-of-the-art warships while also having other business verticals including Ship Repair and Commercial Shipbuilding. The Company invites applications from qualified, talented and dynamic Indian Nationals for the posts of Officers in various grades as indicated below:

(i) Project Superintendent (CGM) (E-8) [Fixed Term]–Technical – 02 Posts (UR-1, OBC-1)
(ii) Project Superintendent (GM) (E-7) [Fixed Term]–Technical – 01 Post (UR)
(iii) Deputy General Manager (E-5) [Fixed Term]– Technical – 06 Posts (UR-3, OBC-1, SC-1, EWS-1)
(iv) Senior Manager (E-4) [Fixed Term]– Technical – 09 Posts (UR-3, OBC-2, SC-2, ST-1, EWS-1)
(v) Manager (E-3) [Permanent] - Finance – 01 Post – ST-01
(vi) Manager (E-3) [Fixed Term]– Medical – 02 Posts (UR-1, OBC-1)
(vii) Manager (E-3) [Fixed Term]– Technical – 01 Post (OBC-1)
(viii) Deputy Manager (E-2) [Fixed Term]-Medical – 01 Post (PWD–OH & OBC)
(ix) Deputy Manager (E-2) [Permanent]-Medical-01 Post (OBC)

The details like General Conditions, eligibility, essential qualification, minimum experience, selection process, how to apply etc. are available in **'Career section'** of GRSE website **www.grse.In** or **https://jobapply.in/grse2024**

(Opening Date for Online Registration: 29 October 2024 & Closing Date for Online registration: 18 November 2024)

Candidates are required to apply only through ONLINE mode. No other means/mode of submission of applications will be accepted.

Any Addendum/Corrigendum will only be published in GRSE website.

"In Pursuit of Excellence and Quality in Shipbuilding"
Visit us at: www.grse.in

EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in Crore)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2024 (Audited)	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2024 (Audited)
Total income from Operations	2,298.86	2,180.48	2,883.64	4,479.34	5,509.28	11,950.40	2,447.52	2,287.13	3,033.27	4,734.65	5,797.11	12,513.65
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
Net profit after tax	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.92	224.03	250.78	429.95	438.15	929.51
Profit is attributable to :												
Owners of the Parent	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.95	224.02	250.73	429.97	438.09	929.57
Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	(0.03)	0.01	0.05	(0.02)	0.06	(0.06)
Total comprehensive income	201.34	176.84	237.01	378.18	399.18	862.39	205.02	224.36	257.35	429.38	445.23	928.98
Equity share capital	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
Other Equity attributable to Owners of the Parent (Excluding Revaluation Reserve)						5,583.66						5,682.82
Earnings Per Share (not annualized)												
(Face Value of ₹2/- each)												
(a) Basic (in ₹)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88
(b) Diluted (in ₹)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88

NOTES :

1. The above standalone and consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th November 2024. The Statutory Auditors of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter and half year ended 30th Sept. 2024.
2. The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ircon.org.
4. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period / year.

Place: New Delhi
Date: 7th November, 2024

For and on behalf of Ircon International Limited
Sd/-
Hari Mohan Gupta
Chairman & Managing Director
DIN- 08453476

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Government of India Undertaking)
Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017; Tel: +91-11-26530266; Fax: +91-11-26522000/26854000
E-mail: investors@ircon.org; Website: www.ircon.org; Corporate Identity Number: L45203DL1976GOI008171

SC: DRI officers can recover customs dues

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 7

IN A SIGNIFICANT decision impacting customs enforcement across the country, the Supreme Court held on Thursday that officers of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) have the authority to seek recovery of duties on goods already cleared for import by the customs department.

Allowing a review plea of the customs department, a bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra overturned the apex court's 2021 ruling, penned by the then CJI S A Bobde, that DRI officers are not "proper officers" for issuing notices under section 28 of the Customs Act.

Writing a 162-page judgment for the bench, Justice Pardiwala upheld the authority of DRI officers to issue show-cause notices and recover duties under the Act. The verdict came as a boost to the customs department, which has several proceedings related to duty dues pending.

"The petition seeking a review of (the) Canon India (judgment) is allowed for the following reasons.... In other words, the judgment in Canon India was rendered without looking into the circular and notification, therefore seriously affecting the correctness of the same. The decision in Canon India failed to look into the statutory scheme," it said The court also issued specific instructions to streamline the handling of the pending cases challenging show-cause notices issued by DRI officers.

On March 9, 2021, a three-judge bench headed by the then CJI Bobde had quashed the DRI's show-cause notices issued to private firms, including Canon India Private Limited, seeking payment of duty and the consequential confiscation of goods, demand of interest and imposition of penalty under the Customs Act.

Centre doubles fines for stubble burning

SANDIP DAS
New Delhi, November 7

AMIDST A SHARP fall in incidents of firm fire this season, the environment ministry has doubled the penalty for stubble burning in the national capital region to ₹5,000 for those with land holding of less than two acres and to ₹10,000 for those having land between two and five acres. Farmers with land of more than five acres will pay an environmental compensation of ₹30,000 as against earlier ₹15,000.

The environment ministry announced amendments to the rules concerning the imposition, collection and utilisation of environmental compensation for stubble burning. Over the past several days, the region has witnessed a thick layer of smog, while the overall air quality continued to remain in the 'very poor' category. On Thursday, Delhi's average air quality index (AQI) was at 377 at 4 PM.

There has been a 58% decline in burning of paddy straw during September 15-November 6 in six northern states. Punjab has so far recorded a 74% drop in stubble burning incidents in 2024 as compared to the same period last year, while neighbouring Haryana has seen a 44% drop.

Anti-dumping duty on solar glass from China, Vietnam recommended

FE BUREAU
New Delhi, November 7

THE TRADE DEFENCE arm of the government — Directorate General of Trade Remedies (DGTR) — has recommended imposition of anti-dumping duty of up to $677 per metric tonne on imports of glass used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications from China and Vietnam. The recommendation came on a complaint by the domestic manufacturers led by Borosil Renewables.

The provisional findings of the DGTR has found that below-cost imports from these two countries are forcing domestic producers to sell at a loss. The domestic industry has suffered from under-utilised capacities throughout the period under investigation and sold a very small share of the demand. The imports have dominated the market share throughout the period and the average inventories of the domestic industry have increased.

The investigation period was from 2020-21 to 2022-23. During this period, imports of solar glass increased to 795,555 MT from 158,799 MT in 2020-21. The ministry of finance takes a final call on the imposition of the duty.

EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in Crore)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2024 (Audited)	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2024 (Audited)
Total income from Operations	2,298.86	2,180.48	2,883.64	4,479.34	5,509.28	11,950.40	2,447.52	2,287.13	3,033.27	4,734.65	5,797.11	12,513.65
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	248.67	234.31	299.10	482.98	526.70	1,155.54	262.34	281.81	328.36	544.15	591.41	1,261.13
Net profit after tax	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.92	224.03	250.78	429.95	438.15	929.51
Profit is attributable to :												
Owners of the Parent	202.22	176.51	230.44	378.73	392.10	862.90	205.95	224.02	250.73	429.97	438.09	929.57
Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	(0.03)	0.01	0.05	(0.02)	0.06	(0.06)
Total comprehensive income	201.34	176.84	237.01	378.18	399.18	862.39	205.02	224.36	257.35	429.38	445.23	928.98
Equity share capital	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
Other Equity attributable to Owners of the Parent (Excluding Revaluation Reserve)						5,583.66						5,682.82
Earnings Per Share (not annualized)												
(Face Value of ₹2/- each)												
(a) Basic (in ₹)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88
(b) Diluted (in ₹)	2.15	1.88	2.45	4.03	4.17	9.17	2.19	2.38	2.67	4.57	4.66	9.88

NOTES :
1. The above standalone and consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th November 2024. The Statutory Auditors of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter and half year ended 30th Sept. 2024.
2. The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ircon.org.
4. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period / year.

Place: New Delhi
Date: 7th November, 2024

For and on behalf of Ircon International Limited
Sd/-
Hari Mohan Gupta
Chairman & Managing Director
DIN- 08453476

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Government of India Undertaking)
Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017; Tel: +91-11-26530266; Fax: +91-11-26522000/26854000
E-mail: investors@ircon.org; Website: www.ircon.org; Corporate Identity Number: L45203DL1976GOI008171

Extract of unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2024

(Rs. in Cr.)

PARTICULARS	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.09.2023	Half Year Ended 30.09.2024	Half Year Ended 30.09.2023	Year Ended 31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	3634.02	3611.61	2940.70	7245.63	6273.73	13195.22
Operating Earning before Interest, Depreciation and Amortisation, Share in Profit of associates and Joint Venture and Tax	406.65	487.77	307.14	894.42	721.03	1570.14
Net Profit before tax	306.80	374.13	133.40	680.93	382.31	939.68
Net Profit for the period after tax	215.68	276.12	481.97	491.80	683.86	1029.00
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	308.82	309.99	515.20	618.81	729.22	1095.92
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)	278.04	278.04	255.08	278.04	255.08	278.04
Other Equity	—	—	—	—	—	9368.63
Earnings Per Share (EPS) (not to be annualised)						
(a) Basic (Rs.)	7.76	9.93	18.89	17.69	26.81	39.54
(b) Diluted (Rs.)	7.73	9.89	18.89	17.62	26.81	39.46

Extract of unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2024

(Rs. in Cr.)

PARTICULARS	STANDALONE					
	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.09.2023	Half Year Ended 30.09.2024	Half Year Ended 30.09.2023	Year Ended 31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	1694.43	1558.67	1455.85	3253.10	3152.02	6668.45
Net Profit before tax	147.20	224.37	65.25	371.57	195.89	456.04
Net Profit for the period after tax	108.36	162.86	50.72	271.22	161.05	351.40

1. The above extracts are the detailed format of the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website: www.shyammetalics.com
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on November 7, 2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 7, 2024.

Place: Kolkata
Date: 07.11.2024

For & on the behalf of the Board
Shyam Metalics and Energy Limited
Sd/-
Mahabir Prasad Agarwal
Chairman
DIN - 00235780

SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED
Registered Office : Trinity Tower, 7th Floor, 83 Topsia Road, Kolkata - 700 046.
Ph: 033-4016-4000/4001, E-mail: compliance@shyamgroup.com, website: www.shyammetalics.com, CIN: L40101WB2002PLC095491

Organized by
INDIAN CHAMBER OF COMMERCE
INDIA 2047
Principal Partner
WORLD GOLD COUNCIL

6th ICC Gems & Jewellery SUMMIT 2024

Innovate, Elevate, Globalise: Pioneering New Horizons for India's Gems and Jewellery Industry
8 th November, 2024 Friday | India Habitat Centre, New Delhi | Flagship Conference

EMINENT SPEAKERS

Chief Guest
Mr. Jitin Prasada
Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry, Government of India

Guest of Honour
Mr. Atul Kumar Tiwari, IAS
Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India

Mr. Saiyam Mehra
Chairman, All India Gem & Jewellery Domestic Council
Mr. Vinod Bamalwa
Chairman, ICC National Expert Committee on Jewellery & Lifestyle; Director, Nemichand Bamalwa & Sons
Mr. Suvankar Sen
Co-Chair, ICC National Expert Committee on Jewellery & Lifestyle; Managing Director & CEO, Senco Gold Limited
Mr. Ashok Gautam
MD & Chief Executive Officer, India International Bullion Exchange (IIBX)
Dr. Chetan Kumar Mehta
Chairman & MD, Laxmi Diamonds, President- Jewellery Division, India (IBJA); President, Jewellers Association Bangalore
Mr Sabyasachi Ray
Executive Director, Gems & Jewellery Export Promotional Council
Mr. Yogesh Singhal
Chairman, All Bullion & Jewellers' Association
Ms. Nirupama Soundararajan
Co-founder & CEO, Policy Consensus Centre
Mr. Samar Kumar De
Director, Guinea Emporium
Mr. Ashok Seth
Chairman - Norther Region, GJEPC
Mr. Sripal Dholakia
Director, Shreekunj AAI Limited

Mr. Pramod Agrawal
Chairman, National Gem & Jewellery Council of India
Mr. Sachin Jain
Regional CEO - India, World Gold Council
Prof. Sundaravalli Narayanaswami
Chairperson, The India Gold Policy Centre
Mr. Rajeev Garg
Executive Director & CEO, Gem & Jewellery Skill Council of India (GJSCI)
Mr. Rajiv Kumar Saxena
Chief General Manger, Commercial Clients Group-I, SBI
Dr. Suruchi Mittar
Senior Vice President & Chief Industry Officer - Non-Tech Sector, Invest India
Mr. D. D. Karel
Director, N. M. Karel & Sons Pvt. Ltd.
Mr. Sunil Kashyap
Director, FinMet Pte Limited
Mr. Rahul Gupta
Associate Vice President - Intermediary Relationships, National Stock Exchange of India Ltd.
Mr. Soumik Roychowdhury
Director, MPJ Jewellers
Mr. Anil Sankhwal
Chairman, Indian Institute of Gem & Jewellery & CoA Member, GJEPC
Mr. Nisheeth Nayar
Director, Chandrani Pearls

PLATINUM PARTNER: PLATINUM GUILD INTERNATIONAL
GOLD PARTNERS: GJC, GJEPC INDIA, TANISHQ
SUPPORTING PARTNER
EXCHANGE PARTNER: NSE
JEWELLERY PARTNERS: NCB, SENCO
SILVER SPONSORS: FINMET, IIBX, GIA, ISIS, MPJ
PROMOTIONAL PARTNER: SVAR
KNOWLEDGE PARTNER: POLICY CONSENSUS CENTRE